the beneficiary is to be allowed to select an animal of his choice and he can himself make payment to the supplier direct against cash receipt. The acquisition of the animal would be verified by the field staff of bank.

Reaction of IFWJ to Bachawat Wage Board

285. SHRI DHULESHWAR MEENA:
SHRI CHATURANAN MISHRA:
SHRI N. E. BALARAM:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian Federation of Working Journalists has impressed upon Government that serious industrial unrest in newspaper organisations would ensue if Government accept the irrational and anti-labour recommendations of the Bachawat Wage Board regarding interim relief;

(b) whether it is also a fact that IFWJ has demanded the replacement of Shri Bachawat as Chairman of the Wage Board; and

(c) if so, what is Government"s reaction thereto and what decision, if any, has been taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) and (b)Yes, Sir.

(c) The Government have notified the interim relief 15 per cent of basic wages subject to minimum of Rs. 90|- p.m. as against a rate of 7.5 per cent subject to a minimum of Rs. 45|- p.m. recommended by Wage Boards.

देश में कपड़ा मिलें

286. **श्री अीर्ज़ा इर्शाद बेग** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने क कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य-वार कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है ;

(ख) सरकार कितनी मिलें चलाती है; और

(ग) कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए किन-किन उपायों पर विचार किया जा रहा है और इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) मई 1986 के अन्त तक देश में सूती वस्त्र मिलों (राज्य-वार) की संख्या निम्नोक्त प्रकार है :—

राज्य	मिलों की संख्या
आंध्र प्रदेश	55
आसाम	2
बिहार	6
गुजरात	116
हरियाणा	17
जम्मू और काश्मीर	1
कर्नाटक	43
केरल	28

राज्य	मिलों की संख्या
मध्य प्रदेश	24
महाराष्ट्र	114
उड़ीसा	9
पंजाब	20
राजस्थान	34
तमिलनाडु	439
उत्तर प्रदेश	49
पश्चिमी बंगाल	42
दिल्ली	4
पांडिचेरी	6
गोवा	1
हिमाचल प्रदेश	3
मनीपुर	1
	1014

(ख) अपने-अपने अभिकरणों की मार्फत केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों दोनों द्वारा चलाई जा रही सूती वस्त्र मिलों की संख्या 164 है ।

(ग) वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए जून, 1985 में सरकार द्वारा घोषित वस्त्र नीति के अनुसार सरकार द्वारा कई उपाय उठाए गए हैं ।

उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं :—

(1) वस्त्र उद्योग को 31 मार्च 1986 तक आई डी बी आई द्वारा 439.43 करोड़ रु. की सुलभ ऋण की अदायगी ।

(2) अगले पांच वर्षों के दौरान वस्त्र उद्योग की आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 750 करोड़ रु. का आधुनिकीकरण कोष का सृजन ।

(3) पूर्ण फाइबर लोचशीलता की अनुमति ।

(4) आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं तथा आधुनिकीकरण के प्रकार का, जिसे वस्त्र उद्योगद्वारा अपनाया जाना चाहिए, पता लगाने के लिए अधुनिकीकरण पर एक राष्ट्रीय स्तर की स्थायी सलाहकार समिति की स्थापना ।

(5) सम्भाव्य तौर पर अर्थक्षम वस्त्र मिलों के लिए बनाये जाने वाले पुनःस्थापन पैकेज तैयार करने तथा प्रबन्ध करने के लिए एक नोडीय अभिकरण की स्थापना ।

(6) अच्छी क्वालिटी की मशीनरी बनाने के लिए स्वदेशी वस्त्र मशीनरी विनिर्माता क्षेत्र को प्रोत्साहन ।

(7) स्वदेश में न बनायी जाने वाली अत्याधुनिक वस्त्र मशीनों के ओ जी एल लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की अनुमति ।

(8) निर्यात बाध्यता से सम्बद्ध बड़े पने वाले शटल रहित करघों तथा रोटर स्पिनिंग मशीनों के रियायती आयात शुल्क पर आयात की अनुमति ।

देश में हथकरघा-एककः

287. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में हथकरघा-एककों की राज्य-वार संख्या कितनी है; इन एककों में कितने व्यक्ति नियोजित हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने नये एककों को खोला या बन्द किया गया है ;

(ख) इस समय हथकरघा-क्षेत्र का वार्षिक उत्पादन कितना है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, इस क्षेत्र द्वारा जनता कपड़ा का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया ; और

(ग) क्या सरकार हथकरघा-क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान): (क) देश में हथकरघा क्षेत्र विकेन्द्रीकृत है और कुटीर उद्योग के रूप में चलाया जाता है । इसलिए गत तीन वर्षों के दौरान खोले गए अथवा बन्द हुए हथकरघा एककों के कोई आंकड़े नहीं हैं । अलग-अलग समय पर विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर देश में हथकरघों की कुल संख्या अनुमानतः लगभग 30 लाख है । हथकरघों का राज्य-वार विवरण दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । (नीचे देखिये) 1985-86 के दौरान हथकरघा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या अनन्तिम तौर पर अनुमानतः 78.5 लाख है ।

(ख) 1985-86 के दौरान हथकरघा क्षेत्र में अनन्तिम तौर पर अनुमानतः 36800 लाख मीटर का उत्पादन हुआ है । गत तीन वर्षों के दौरान जनता कपड़े का उत्पादन निम्नोक्त प्रकार हुआ है:-

वर्ष	उत्पादन लाख वर्गमीटर में
1983-84	3483.40
1984-85	3567.70
1985-86	3981.20 (अन्तिम)

(ग) भारत सरकार हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिये निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित करती रही है:-

(1) प्राथमिक सहकारी समितियों में शेयर पूंजी अंशदान के लिए हथकरघा बुनकरों को ऋण सहायता ।

(2) प्राथमिक सहकारी समितियों, एपैक्स सहकारी समितियों और राज्य हथकरघा विकास सहकारी समितियों और राज्य हथकरघा विकास निगमों को शेयर पूंजी सहायता ।

(3) प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय उपदान ।

(4) हथकरघा सहकारी समितियों और राज्य हथकरघा विकास निगमों के लिए आधुनिकीकरण सहायता ।

(5) करघा-पूर्व तथा करघा-पश्चात् संसाधन सुविधाओं की स्थापना के लिए सहायता ।

(6) जनता कपड़ा योजना ।

(7) विशेष छूट योजना ।

(8) हथकरघा बुनकर सहकारी क्षेत्र में कताई मिलों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता ।

(9) विशेष पर्वतीय क्षेत्र विकास परियोजनाएं ।

(10) थ्रिफ्ट कोष योजना ।

(11) कार्यशाला-सह-आवास योजना ।